रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243302
CG-DL-E-31012023-243302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

फा. सं. पी-44020/3/2021-डीबीए-II.—केन्द्र सरकार 'केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम, 1997' शीर्षक वाली भारत सरकार की दिनांक 19 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 6(2)98-डीबीए-II में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। यह संशोधन 18.06.2014 से प्रभावी होगा।

2. दिनांक 18.06.2014 से अनुमत सब्सिडी की सीमा के खंड-5 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"5. अनुमत सब्सिडी की सीमा."

नई इकाइयों के लिए: पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी स्थित सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उनको दी गई कार्यशील पूंजी पर 3% की सीमा तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए: पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाई के मामले में ब्याज सब्सिडी की लागू मात्रा, पर्याप्त विस्तार के बाद वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से ठीक पहले दो वित्तीय

वर्षों के दौरान औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त कार्यशील पूंजी ऋण के औसत के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण में वृद्धि की 3% होगी।

तथापि, एसएलसी द्वारा पहले ही विचार/सिफारिश की जा चुकी इसी प्रकार के ब्याज सब्सिडी दावों को उन्हें पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है।

संदेहों को दूर करने/स्पष्टता के लिए, दिनांक 18.06.2014 के पत्र/परिपत्र में संलग्न/प्रतिपादित गणना की पद्धति लागू होगी।

राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2023

F. No. P-44020/3/2021-DBA-II.–The Central Government hereby makes the following amendment in the Government of India Notification No. 6(2)98-DBA-II dated 19th February 1999 titled ‘Central Interest Subsidy Scheme, 1997’. The amendment shall come to effect from 18.06.2014.

2. W.e.f.18.06.2014 clause 5 of the extent of admissible subsidy shall be read as under:

“5. Extent of admissible subsidy.”

For new units: all eligible industrial units located anywhere in the North East Region shall be given an interest subsidy to the extent of 3 % on the working capital advanced to them by the Scheduled Banks or Central State financial institutions for a maximum period of 10(ten) years from the date of commencement of commercial production.

For existing units undergoing substantial expansion: the quantum of interest subsidy eligible in the case of an existing industrial unit which has gone for substantial expansion will be 3% of the increase in working capital loan over and above the average of the working capital loan availed by the industrial unit during two financial years just preceding the date of commencement of commercial operation after undergoing substantial expansion”.

However, similar interest subsidy claims that have already been considered/recommended by the SLC need not be reopened.

For the removal of doubts/for the sake of clarity, the methodology for calculation as appended/enunciated in the letter/circular dated 18.06.2014 shall prevail.

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA